



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, शुक्रवार, 23 अप्रैल, 2004/3 वैशाख, 1926

---

हिमाचल प्रदेश सरकार  
निर्वाचन विभाग

आदेश

शिमला-171 009, 15 अप्रैल, 2004

संख्या 7-2/2000-ई०एल० एन०.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 3/ई०आई०डी०/2004/न्यायिक-II दिनांक 2 अप्रैल, 2004, जिसमें लोक सभा निर्वाचन-2004 के दौरान

आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,  
मनीषा नन्दा,  
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
हिमाचल प्रदेश।

**भारत निर्वाचन आयोग**

निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001

संख्या 3/4/आई0डी0/2003/न्यायिक-II

2 अप्रैल, 2004

**आदेश**

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उस अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान बनाया जाए; और

2. यतः, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और मतदान के समय उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटोग्राफ सहित फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निर्देश देने का अधिकार देता है; और

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबन्ध 1 है कि जिन निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबन्ध के अधीन निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना पहचान पत्र जारी करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर वोट डालने से उन्हें मना किया जा सकता है; और

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबन्धों का सम्मिलित और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है वहां दोनों का ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यतः निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यतः, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र कार्यक्रम जारी करने के लिए कार्यान्वयन शुरू किया गया है, सभी राज्यों के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी हो या वे निर्वाचन-क्षेत्र के बाहर चले गए हों और उन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र कहीं और से प्राप्त कर लिए हों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों में चक्रों द्वारा अधिक संख्या में निर्वाचकों को पहचान-पत्र जारी किए हैं; और

में हुए केरल, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी की विधान सभाओं के लिए हुए निर्वाचनों, गत वर्ष 2002 में हुए मणिपुर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा और गुजरात विधान सभा के लिए हुए निर्वाचनों और पिछले वर्ष हुए हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इस बीच हुए बहुत से उप-निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, मतदान करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन शेष निर्वाचकों जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

8. यतः, उच्चतम न्यायालय को, आर० डी० भंडारी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में फोटो पहचान-पत्र के प्रयोग सम्बन्धी आयोग के उपरोक्त निदेश से अवगत कराया गया और उच्चतम न्यायालय ने मतदाता फोटो पहचान-पत्र सम्बन्धी सभी याचिकाएं 17 अगस्त, 2000 को खारिज कर दी; और

9. यतः, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्रमशः 2001 की रिट अर्जी सं० 2598, 2601 और 2637 तथा 2000 की रिट अर्जी सं० 3772 और 2001 की रिट अर्जी सं० 5235, 2002 की रिट अर्जी सं० 294 तथा 2002 की रिट अर्जी सं० 5401 में आयोग के उपर्युक्त निदेशों को क्रमशः मान्य ठहराया है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एस० एल० पी० नं० 3820-21/2002 पर एक अन्तरिम आदेश पारित किया जिसमें यह निदेश दिया कि जनवरी-फरवरी 2002 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान के सम्बन्ध में आयोग के आदेश लागू किए जाएं।

10. यतः, अब, सभी सम्बद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी निर्वाचक जिन्हें मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें लोक सभा के तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और सिक्किम की विधान सभाओं के चालू साधारण निर्वाचन एवं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में उप-निर्वाचनों में, जिन्हें लोक सभा के साधारण निर्वाचन के साथ-साथ आयोजित किया जा रहा है और जिन्हें 24 मार्च, 31 मार्च, 8 अप्रैल और 16 अप्रैल, 2004 को अधिसूचित किया जा चुका है/किया जाना निर्धारित है को मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों में मत डालने के लिए आते समय और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय इन पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

11. निर्वाचन आयोग इस बात को दोहराते हुए यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के अधीन जारी निर्वाचकों को पहचान-पत्रों के माध्यम से मतदान केन्द्र पर अपनी पहचान स्थापित करनी होगी। हालांकि उन्हें मतदान के उद्देश्य के लिए मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग प्रारम्भिक चरणों में है, आयोग इस मामले में पर्याप्त सतर्कता के रूप में चालू साधारण निर्वाचन में उन शेष निर्वाचकों को मत देने की अनुमति देगा, जिन्हें मतदाता पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, बशर्ते उनकी पहचान पीठासीन अधिकारी या दूसरे मतदान अधिकारी, जिसे पीठासीन अधिकारी ने प्राधिकृत किया है, की संतुष्टि में अन्यथा स्थापित हो

जाती है, उक्त उद्देश्य के लिए उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे निर्वाचकों की पहचान सिद्ध करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं :-

- (i) पासपोर्ट
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स
- (iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन)
- (iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र।
- (v) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (31-3-2004 को या उससे पूर्व खोला गया खाता)
- (vi) छात्र पहचान-पत्र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा 31-3-2004 अथवा उससे पूर्व जारी।
- (vii) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज आदि
- (viii) 31-3-2004 को अथवा उससे पूर्व जारी राशन कार्ड
- (ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-3-2004 अथवा उससे पूर्व जारी अ.जा./अ.ज.जा./अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।
- (x) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश।
- (xi) रेलवे पहचान-पत्र
- (xii) स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र
- (xiii) शस्त्र लाइसेंस
- (xiv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2004 अथवा उससे पूर्व जारी शारीरिक रूप विकलांग प्रमाण-पत्र।

12. पहचान के लिए उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज उन शेष निर्वाचकों, जिन्हें मतदाता पहचान-पत्र सप्लाई तो किए गए हैं किन्तु जिन्हें वे ऐसे कारणों से प्रस्तुत करने में असफल हैं जो उनके वश में नहीं हैं, पर भी लागू होंगे।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर गिनाए गए किसी दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होती है, की परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जानी चाहिए, परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती है।

आदेश से,

(के० एफ० विल्फ्रेड),  
सचिव।

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi-110001.

**No.3/4/ID/2004/J.S.II.**

**Dated : 2<sup>nd</sup> April, 2004.**

**ORDER**

1. Whereas, section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electoral Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electoral Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of the States have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors, many of whom might have been

dead or might have moved out of the constituencies and obtained their Electoral Identity Cards elsewhere; and

7. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March, 2000, and to the Legislative Assemblies of Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Pondicherry in April-May, 2001, and to the Legislative Assemblies of Manipur, Punjab, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Goa and Gujarat held in 2002 and at the Legislative Assembly elections held in Himachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Tripura, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Mizoram and Delhi last year, and at a number of bye-elections held in between, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

8. Whereas, the Supreme Court was apprised of the direction of the Commission regarding use of EPIC, in *R. D. Bhandari & Others Vs. Election Commission of India & Others*, and the Supreme Court was thereupon pleased to dismiss on 17-8-2000 all petitions relating to the issue of EPICs; and

9. Whereas, the Andhra Pradesh High Court and Punjab & Haryana High Court, Madras High Court, High Court of Madhya Pradesh and High Court of Karnataka have also upheld the above direction of the Commission regarding compulsory identification of electors, in Writ Petition Nos. 2598, 2601 and 2637 of 2001, Writ Petition No. 3772 of 2000, Writ Petition No. 5235 of 2001, Writ Petition 294 of 2002 and Writ Petition 5401 of 2002 respectively, and the Hon'ble Supreme Court in the interim order passed on in SLP No. 3820-21/2002, directed that the Commission's Order regarding identification of electors at the general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January-February, 2002 would be implemented.

10. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in all States and Union Territories who have been issued with their EPICs, shall have to produce these cards to exercise their franchise, when they come to the polling stations for voting at the current General Election to the House of the People and the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa and Sikkim and in the bye-elections to the State Legislative Assemblies in Assam, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, Mizoram, NCT of Delhi, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, which are being held simultaneously with the general election to the House of the People, and which have been/are scheduled to be notified on 24th March, 2004, 31st March, 2004, 8th April, 2004, and 16th April, 2004.

11. The Election Commission wishes to make it clear at the cost of repetition, that the electors will have to establish their identity at the polling stations by means of the EPICs issued to them under the authority of the Election Commission. However, since the use of EPICs for the purpose of voting is still in its early stages, the Commission, as a matter of

abundant caution, will permit the odd electors who have not obtained their EPICs, to vote at the current General Election, provided their identity is otherwise established to the satisfaction of the Presiding Officer or such other Polling Officer as is authorised by the Presiding Officer in this behalf. For the above purpose, they will have to produce some documentary evidence for establishing their identity, and the Commission has prescribed the following alternative documents for establishing the identity of such electors :—

- (i) Passports
- (ii) Driving Licenses
- (iii) Income Tax Identity (PAN) Cards
- (iv) Service Identity Cards issued to its employees by State/Central Government Public Sector Undertakings, Local Bodies or other Private Industrial Houses.
- (v) Bank/Kisan/Post Office Passbooks (Accounts opened on or before 31st March, 2004).
- (vi) Student Identity Cards issued by Recognised Educational Institutions on or before 31st March, 2004.
- (vii) Property Documents such as Pattas, Registered Deeds, etc.
- (viii) Ration Cards issued on or before 31st March, 2004
- (ix) SC/ST/OBC Certificates issued by competent authority on or before 31st March, 2004.
- (x) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order.
- (xi) Railway Identification Cards.
- (xii) Freedom Fighter Identity Cards.
- (xiii) Arms Licenses
- (xiv) Certificate of Physical Handicap by Competent Authority issued on or before 31st March, 2004.

12. The above alternative documents for identification will also apply in respect of such of the odd electors, who have been supplied with Electoral Identity Cards, but are not able to produce them for reasons beyond their control.

13. It is clarified that any document as enumerated above, which is available only for the Head of Family, shall be allowed for the purpose of identification of other members of the family. Similarly, any document in the name of any other member of the family could also be used for identification of other members, provided the other members can be identified on the basis of such document.

By order,

(K. F. Wilfred)  
Secretary.